

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
एवं कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 31 अगस्त, 2016

विषय: जनपद-चमोली के गोपेश्वर में बेस चिकित्सालय के निर्माण हेतु रेशम विभाग की भूमि चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक-19.07.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जनपद-चमोली के गोपेश्वर में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में बेस चिकित्सालय के निर्माण हेतु रेशम विभाग के स्वामित्व की भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेशम विभाग के गोपेश्वर फार्म की कुल 2.721 है० भूमि में से बेस चिकित्सालय हेतु 1.41 है० भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निम्नलिखित निर्णयानुसार एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-260/वित्त अनुभाग-2/2002, दिनांक 15 फरवरी, 2002 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. रेशम विभाग के गोपेश्वर फार्म की कुल 2.721 है० भूमि में से बेस चिकित्सालय हेतु 1.41 है० भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी, परन्तु बेस चिकित्सालय हेतु बजट पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, इसलिए बेस चिकित्सालय गोपेश्वर के लिए जब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ/बजट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक रेशम विभाग के द्वारा उक्त रेशम फार्म की भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
2. रेशम विभाग को अपनी गतिविधियों को विशेषकर शहतूती रेशम को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए रेशम विभाग की भूमि के सापेक्ष आवंटित की जा रही जिला प्रशासन जनपद चमोली रेशम विभाग को शहतूत वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त समतुल्य भूमि चिन्हित कर शीघ्र आवंटित कराएगा तथा रेशम केन्द्र की स्थापना हेतु वांछित धनराशि का प्रावधान उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जायेगा, इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुपूरक मांगों के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था कराई जायेगी।

3. जिन परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।
4. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।
5. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अन्य सरकारी भूमि सड़क निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन को निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/ अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली गई है।
6. हस्तान्तरित भूमि को प्रस्तावित कार्य के इतर किसी भी प्रयोग में लाये जाने पर आंक्टन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)

अपर मुख्य सचिव

एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या-1015/XVI-2/16/17(10)/2015 टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
- 3- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा० रेशम विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सचिव, राजस्व/वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- जिलार्धिकारी, चमोली।
- 9- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
- 10- निदेशक, रेशम विकास विभाग, प्रेमनगर, देहरादून।
- 11- उप निदेशक, रेशम, गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर।
- 12- एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वि.कु.श्रीवास्तव)

(विकास कुमार श्रीवास्तव)

अनु सचिव।